बेवरेज सेक्टर पर ध्यान देकर खुदरा विक्रेताओं की आय दोगुनी करना

अप्रैल 2023

हंसा रिसर्च (आरके स्वामी समूह का हिस्सा) द्वारा

जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए कई बयानों से स्पष्ट है, भारत की आकांक्षाएं राष्ट्रीय गौरव और आत्म-सम्मान के लिए हैं। भारत का लक्ष्य अपना खुद का "बाजार" विकसित करके अगले 25 वर्षों में "अमृत काल" की उपलब्धि प्राप्त करना है। हम इसी कोशिश प्रयास के तहत बेवरेज उद्योग पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस श्वेत पत्र को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सेक्टर पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि इसमें भारत अन्य देशों की बजाय ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सके और अपने आप को विश्व बाजार में स्थापित कर सके।

इस श्वेत पत्र के माध्यम से, हम यहाँ नीचे दिए गए कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं:

- भारत को दुनिया की बेवरेज की राजधानी बनाना
- थमे हुए से बेवरेज सेक्टर में नवाचार लाना।
- बेवरेज पर ध्यान केंद्रित करके खुदरा विक्रेताओं की आय को दोगुनी करना
- किसानों की आय बढ़ाना और रोजगार पैदा करना
- खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ाना
- असंगठित / जाली अर्थव्यवस्था से संगठित (कार्पोरेट) अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना।
- सरकार के लिए ज्यादा राजस्व जुटाने के अवसर पैदा करना।

सबसे पहले, हम भारत में बेवरेज उद्योग का परिचय प्राप्त करते हैं जिसमें बिना शराब वाले रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों के उद्योग सेगमेंट पर खास ध्यान दिया जाता है। इस सेगमेंट में बोतलबंद पानी, गैर-कार्बनेटेड पेय (जैसे फलों के रस आदि) और कार्बनेटेड पेय शामिल हैं। 2022 के आंकडों के अनुसार, कारोबार के नजरिए से यह सेगमेंट लगभग 58 हजार करोड़ रुपये का है और इसमें 2021 के मुकाबले लगभग 30% की बढ़त देखी गई है। बेवरेज की श्रेणी के भीतर किसी भी सेगमेंट की उपभोक्ताओं तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच केवल 40% है: सभी किराना स्टोरों की कुल संख्या में से केवल 40% स्टोरों पर बोतलबंद पानी उपलब्ध है, जबकि 39% स्टोरों पर कार्बनेटेड पेय उपलब्ध है। गैर-कार्बनेटेड पेय पदार्थ (फलों के रस, आदि सहित) भारत में अभी भी केवल 32% आउटलेट्स पर ही मिल पाते हैं ।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि पूरे देश में किराना स्टोरों पर उपभोक्ताओं को गैर-कार्बनेटेड और कार्बनेटेड पेयों के अलावा पीने का साफ़ पानी मिलना ही चाहिए। अन्य एफएमसीजी उत्पादों के विस्तार के मद्देनजर इस सेक्टर में विस्तार के लिए बहुत सारे अवसर हैं। चिंताजनक बात यह है कि कुल बेवरेज सेगमेंट में संगठित सेक्टर की बिक्री केवल 20% है और शेष जाली या असंगठित सेक्टर से होती है जहां साफ़-सफाई या इससे सामान्य जनता के स्वास्थ्य से तो खिलवाड़ होता ही है साथ ही जो राजस्व सरकार को मिल सकता था वह भी नहीं मिल पाता। हमारे अनुमानों के अनुसार, सरकार इस सेक्टर से अपने राजस्व का कम से कम 1% भी नहीं कमा पाती। यदि 20% असंगठित सेक्टर भी संगठित सेक्टर में बदल जाए तो इससे सरकार का राजस्व बहुत अधिक बढ़ सकता है।

हमारे अनुमानों से अनुसार वर्तमान में यह सेगमेंट किसी खुदरा विक्रेता की आय में लगभग 11% योगदान देता है और सरकार के राजस्व में 1% से भी कम योगदान ही दे पाता है। यदि हम इस सरकारी राजस्व को प्रति व्यक्ति के हिसाब से बाँटें, तो 2019 में भारत का प्रति व्यक्ति राजस्व केवल 729 रुपये या 8.89 अमेरिकी डॉलर था। जब हम इस संख्या की तुलना अन्य सेक्टर से मिलने वाले राजस्व से करते हैं तो हमे यह साफ दिखाई देता है कि इस सेक्टर से सबसे कम राजस्व पैदा होता है:

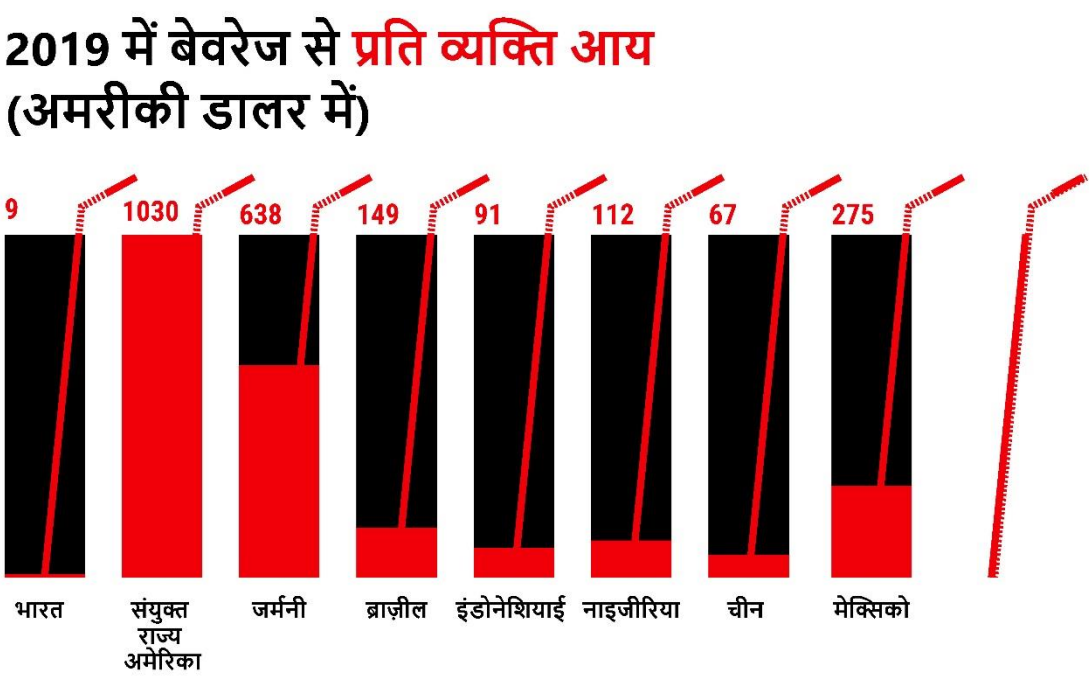

भारत में अन्य सेक्टरों की तुलना में इस सेक्टर से सरकारी राजस्व बहुत कम मिलने के कई कारण हैं। इस सेगमेंट से कम राजस्व मिलने का एक मुख्य कारण असंगठित सेक्टर के विक्रेताओं और जाली उत्पादों की मौजूदगी होना है। अनुमानों के अनुसार, बेवरेज (नॉन-एल्कोहलिक बेवरेज) सेक्टर का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा गैर-कॉर्पोरेट / असंगठित है।

इससे कई चुनौतियां सामने आती हैं:

- सरकार को राजस्व की हानि होती है।
- सामग्री या विनिर्माण / पैकेजिंग / परिवहन की प्रक्रिया में कोई विनियमन नहीं होने से गंभीर स्वास्थ्य खतरा पैदा होता है।
- असंगठित उत्पादन में स्वच्छता के मानकों का ध्यान कम रखे जाने का खतरा होता है जिससे किसी भी तरह की अस्वच्छता पेय पदार्थों में संक्रमण जनित बीमारियां पनपने का कारण बन सकती है।
- असंगठित सेगमेंट का आकार काफी बड़ा है जिससे इस सेक्टर में पैदा हो सकने वाले रोजगार के अवसरों के लिए रुकावटें पैदा हो रही हैं।
- असंगठित सेक्टर के बिक्री बिंदु संगठित सेक्टर के खुदरा विक्रेताओं की आय का हिस्सा खा रहे हैं।

कंपनियों और आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियां

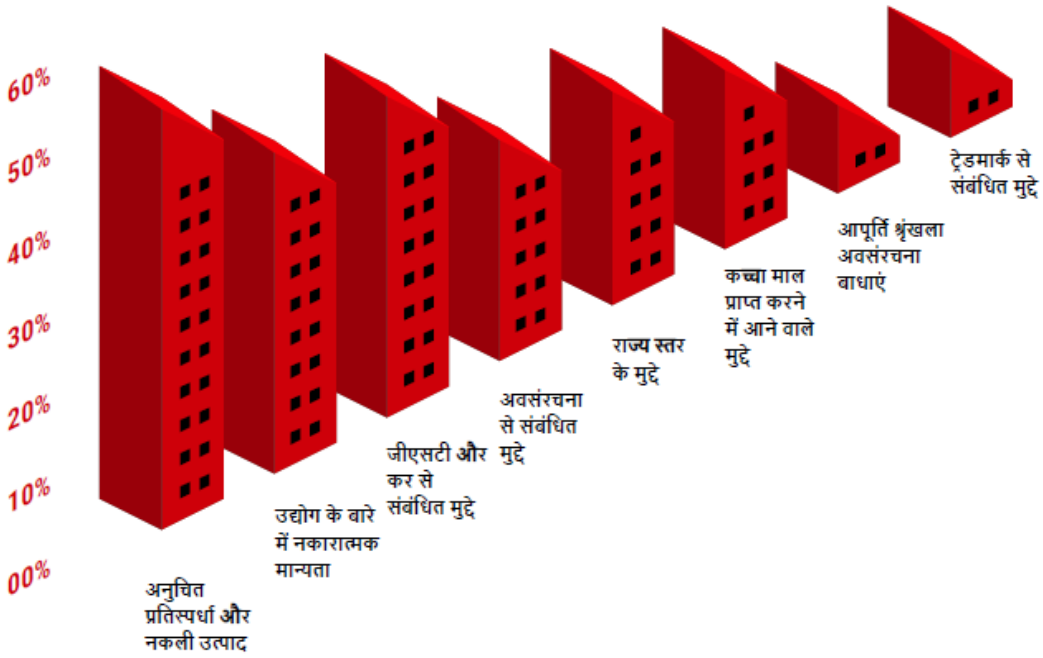

इस सेक्टर से कम राजस्व मिलने का एक अन्य मुख्य कारण जीएसटी और कर से संबंधित मुद्दे हैं। **आइए हम बेवरेज सेक्टर और कुछ अन्य प्रमुख संबंधित सेक्टरों पर वर्तमान जीएसटी दरों को देखें:**

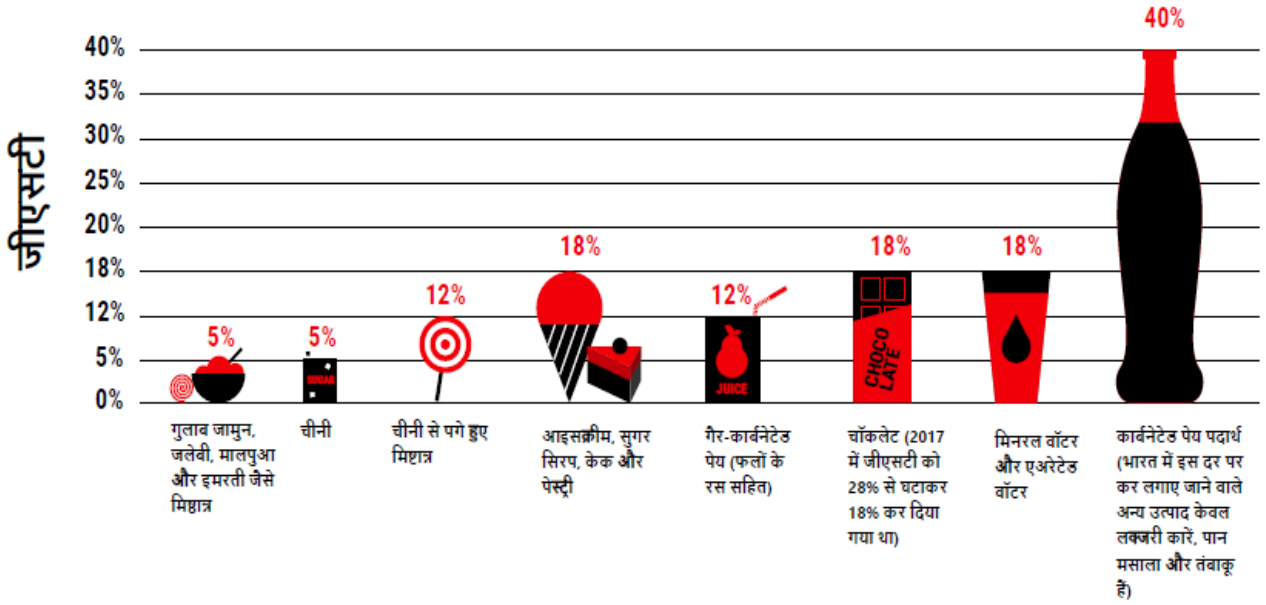

बेवरेज सेक्टर और संबंधित सेक्टरों के लिए वर्तमान में लागू जीएसटी दरों को पूर्व अनुभव और जानकारी के आधार पर निर्धारित किया गया है, लेकिन ये दरें भारत सरकार द्वारा अपने लिए नियत किए गए कुछ उद्देश्यों की विरोधी लगती हैं:

राष्ट्रीय कार्य योजना में 2025 तक मोटापे की महामारी को रोकने का लक्ष्य रखा गया है, और देश को प्रगतिशील विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वस्तुओं पर उनकी पौष्टिकता के आधार पर कर लगाए जाने की रणनीति अपनाई जा रही है।

वर्ल्ड पावर्टी क्लॉक के अनुसार, भारत ने गरीबी को कम करने में अद्भुत प्रगति की है। अगली प्राथमिकता पोषण की स्थिति को सुधारने पर होनी चाहिए।

पोषण आधारित कराधान (जो चीनी या अन्य पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर हो सकता है) भारत सरकार के कई उद्देश्यों में मददगार होगा। पोषण आधारित कराधान 'कम चीनी वाले उत्पादों के लिए कम कर' और 'बिना चीनी वाले उत्पादों के लिए सबसे कम कर' (जो गैर-पोषक मिठास का उपयोग करते हैं) लगाए जाने की रणनीति है।

परिदृश्य	उद्योग का आकार (कार्बनेटेड), ₹ करोड़ *	कर की दर	भारत सरकार का राजस्व (₹ करोड़)	खुदरा वितरक कीआय (₹ करोड़) #	व्याख्या
1 (वर्तमान)	1000	40%	400	110	
2	1300	30%	390	143	यदि कर की दर 30% हो, तो उद्योग पर प्रभाव में 30% की बढ़त होगी, भारत सरकार का राजस्व भी उसी स्तर से बढ़ेगा। हालांकि, खुदरा वितरक की आय बढ़ेगी।
3	2000	25%	500	220	लेकिन यदि हम कर को 25% या 20% तक कम करें, तो उद्योग बड़ी मात्रा में बढ़ सकता है और भारत सरकार के राजस्व पर भी महत्वपूर्ण सकारात्मक असर हो सकता है। इसके अतिरिक्त, खुदरा विक्रेता की आय दोगुनी हो जाएगी।
4	2500	20%	500	275	

*** हिसाब करने के उद्देश्यों के लिए सरलीकरण | - ^ किसी भी कर में कटौती की स्थिति में, उसे अनिवार्य रूप से उपभोक्ता को सीधे पहुंचाना होगा | # यह मानते हुए कि बेवरेज पदार्थों से आय का हिस्सा 11% के बराबर बना रहेगा|**

आगे, हम लाफर वक्र का उपयोग करके इस सेक्टर के लिए आदर्श कर दर का भी निर्धारण कर सकते हैं। कर की आदर्श दर कर को राजस्व ग्राफ पर T* बिन्दु द्वारा दिखाया जाता है। इस बिंदु से परे, कर की दर में वृद्धि कम उपयोगिता पैदा कर रही है या सरकार के राजस्व में कमी का कारण बन रही है। वर्तमान संदर्भ में कर की दर निश्चित रूप से T* से अधिक हो गई है क्योंकि उच्च कर दर न केवल सेक्टर के विकास को रोक रही है (उच्च कर दर ने सेक्टर में किसी भी निवेश या नवाचार को रोक दिया है), बल्कि यह खुदरा-विक्रेता की आय को भी सीमित कर रही है और इससे समग्र रूप से कम राजस्व उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है।

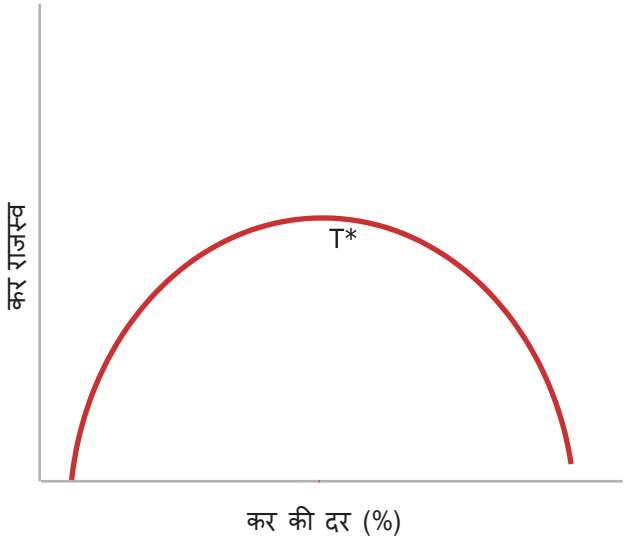

लाफर वक्र

इसके अलावा, इस प्रकार के अत्यधिक कर दर वाले सेक्टर में लाभप्रदता प्राप्त करना किसी भी स्टार्टअप के लिए चुनौतीपूर्ण काम है। सरकारी राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ कर घटाने से इस निष्क्रिय सेक्टर को उत्तेजना मिल सकती है।

जीएसटी घटाने का केवल एक बदलाव करके भारत सरकार अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण बना सकती है। यह सभी को लाभान्वित करने वाली स्थिति होगी:

- **ऐसा करने से सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा।**
- **यह सेक्टर निवेश और नवाचार के लिए खुल जाएगा।**
- **किसानों की आय में वृद्धि होगी - अनुबंध खेती से किसानों को अधिक आय मिलेगी।**
- **नौकरियों में वृद्धि होगी - लोग संगठित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेंगे।**
- **पोषण आधारित कराधान नीति के कारण, स्वास्थ्यकर बेवरेज पदार्थों की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ेगी।**
- **खुदरा विक्रेता की आय में वृद्धि होगी- असंगठित सेक्टर के बिक्री बिंदु कम होंगे और संगठित सेक्टर में वृद्धि होगी, नए मूल्य बिंदु और नए उत्पाद विकल्प प्राप्त होंगें।**
- **निर्यात में वृद्धि होगी- हम दुनिया की बेवरेज राजधानी बनने की क्षमता विकसित कर सकेंगे।**

उपर्युक्त बिंदुओं का समर्थन करने वाले कुछ तथ्य इस प्रकार हैं:

- भारत दूध, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया में कई फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो नॉन-एल्कोहलिक बेवरेज बेवरेज के उत्पादन के कच्चे माल होते हैं। यह केले, आम, चकोतरा, नींबू और पपीते का सबसे बड़ा उत्पादक है । प्रचुर मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध होने से नॉन-एल्कोहलिक बेवरेज पेय पदार्थों के निर्माण में अन्य देशों की तुलना में भारत को सहज ही ज्यादा लाभ मिल सकत है।
- भारत में, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय (MoFPI) के अनुमानों से पता चलता है कि कोल्ड स्टोरेज की कमी, अंतरराज्यीय सीमाओं पर सप्लाई चेन में होने वाली देरी और मार्केटिंग चैनलों का सही तरीके से विकास न होने जैसी प्रसंस्करण और लॉजिस्टिक सुविधाएं पर्याप्त न होने के कारण लगभग 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत फल और सब्जियां सप्लाई चेन में बर्बाद हो जाती हैं। किसानों से कच्चे माल की सीधी खरीद करके नॉन-एल्कोहलिक बेवरेज बेवरेज तैयार करने वाली कई कंपनियां किसानों की आय और भलाई को बढ़ाने में योगदान करती हैं।
- इसके अतिरिक्त, इस सेक्टर में आने वाले विदेशी निवेश की मात्रा एक प्रतिशत से कम हैं और इस सेक्टर के लिए कच्चे माल का मूल उत्पादक होने के बावजूद, भारत इस सेक्टर के उत्पदों का निर्यात करने के मामले में बहुत पीछे है। 2020 में, लगभग कुल 29.89 मिलियन डॉलर मूल्य के निर्यात किए गए थे।
- नॉन-एल्कोहलिक बेवरेज बेवरेज सेक्टर में उत्पादित प्रत्येक ₹ 1 करोड़ मूल्य के उत्पादन के लिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के प्रभावों के कारण अर्थव्यवस्था में कुल 8.9 अतिरिक्त नौकरियां पैदा होती हैं। नौकरियों के संदर्भ में, नॉन-एल्कोहलिक बेवरेज बेवरेज सेक्टर ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 2018-19 में 2,78,970 नौकरियां पैदा कीं, जो राष्ट्रीय रोजगार का 0.06 प्रतिशत हैं। पूरे बेवरेज उद्योग में 2010-11 में रोजगार पाने वाले लोगों की संख्या 127,816 थी जो 2017-18 में बढ़कर 161,065 हो गई, लेकिन अभी भी यह संख्या इस सेक्टर की वास्तविक क्षमता से कम है क्योंकि कच्चे माल का प्रसंस्करण अभी भी बहुत कम हो पा रहा है।
- यद्यपि इस सेक्टर का निर्यात बढ़ा है, लेकिन विकास की दर औसत से निम्न स्तर की ही रही है।

नॉन-एल्कोहलिक बेवरेज बेवरेज कंपनियों की सप्लाई चेन में @Apple किसानों को बेवरेज कंपनियों द्वारा प्रशिक्षण के बाद उसी जिले में स्थित उनके समकक्षों की तुलना में प्रति हेक्टेयर 20 प्रतिशत अधिक उपज मिली, 5 प्रतिशत अधिक कीमतें मिलीं और प्रति फसल मौसम में 59 प्रतिशत अधिक कमाई हुई।

जैसा कि तुमकुर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेख किया गया है, भारतीय किसानों की फलों की बिक्री में वृद्धि से किसानों को मदद मिलेगी, खाद्य भंडारण और परिवहन आदि को बढ़ावा मिलेगा।

नॉन-एल्कोहलिक बेवरेज पेय सेक्टर के भारत से होने वाले निर्यात

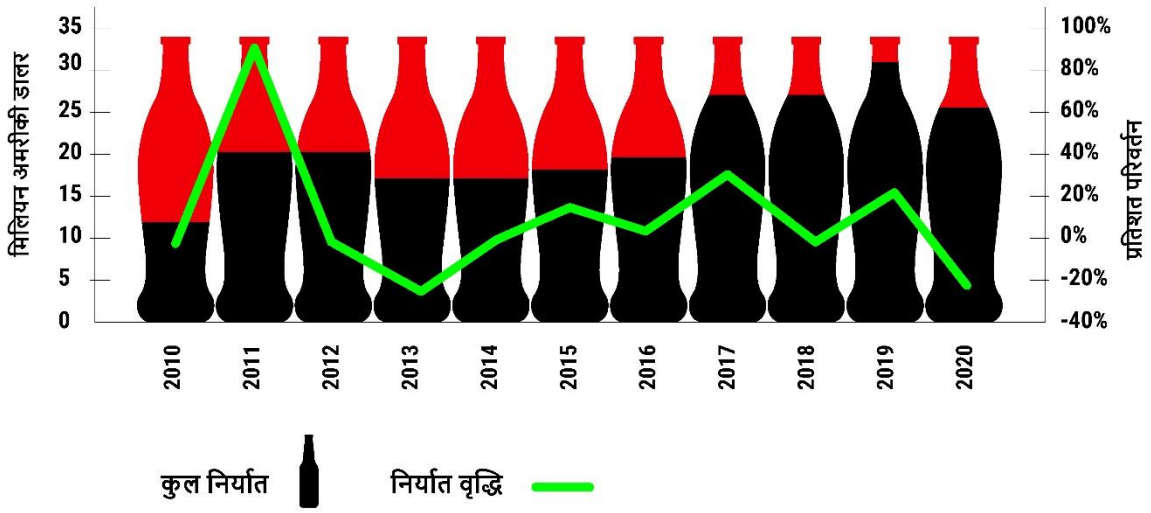

उपभोक्ता की दृष्टि से श्वेतपत्र की आलोचना।

भारत में उपभोक्ताओं को उनके व्यक्तिगत स्तर पर समझना सबसे अच्छा है।जबकि कराधान के विषय में सर्वोत्तम दृष्टिकोणों के बारे में कई अध्ययन उपलब्ध हैं लेकिन इस पर वैश्विक प्रभावों और राय को ध्यान में रखते हुए हमें भारत के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण समझना होगा। 'सर्वोत्तम दृष्टिकोण' के रूप में प्रोत्साहित कई नीतियां भारत में उपभोक्ता व्यवहार को बदलने में सफल नहीं रही हैं । इसलिए, हम न केवल इस सेक्टर से अधिक राजस्व जुटाने में असफल रहे हैं बल्कि आजकल हम सबसे गरीब वर्गों पर करों का ज्यादा बोझ भी डाल दे रहे हैं। इससे इस सेक्टर में गुणवत्ता की कसौटी पर खरे न उतरने वाले जाली उत्पादों को और अधिक प्रोत्साहन मिल जाता है। यह निवेशों को भी रोक देता है और फिर औपचारिक अर्थव्यवस्था और रोजगार पैदा सृजन के अवसरों का नुकसान होता है।

उपभोक्ताओं को जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजिक किए जाने वाले कार्यक्रमों, लेबलिंग आदि के माध्यम से स्वास्थ्य हेतु अनुकूल उत्पादों का उपभोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सब्सिडी नीति के माध्यम से कंपनियों को स्वास्थ्यकर उत्पादों का उत्पादन करने के लिए बढ़ावा दिया जा सकता है। बेवरेज कंपनियों और उनके संघों को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के "ईट राइट अभियान" जैसी सरकारी पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। इसलिए उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ाना और पौष्टिक उत्पादों के लिए ऐसे सकारात्मक हस्तक्षेप या सहयोग-समर्थन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करना बेहतर रहेगा जिनमें सरकार और बेवरेज कंपनियां मिलजुलकर काम कर सकती हों।

"भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह सभी उदाहरणों का अध्ययन करे लेकिन अपनी नीतियां खुद तैयार करे।"

निष्कर्ष

संगठित सेक्टर के विकास से उद्योग और अर्थव्यवस्था बढ़ती है। पाप-कर (अस्वाथ्यकर जीवन शैली को हतोत्साहित करने लिए लगाए जाने वाले कर) देश के सबसे अधिक गरीब लोगों पर असर डाल रहे हैं और उपभोक्ताओं के व्यवहार को बदलने के लिए प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। औसत स्तर की कर-दर, उपभोक्ताओं को स्वस्थ और सुरक्षित उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगी, खुदरा व्यापारियों की आय बढ़ाएगी और स्वस्थ उत्पादों की आकर्षक मूल्य स्तर पर बिक्री संभव करके सरकार के लिए अधिक राजस्व उत्पन्न करेगी। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था को प्रगतिशील बनाने में मदद मिलेगी।

भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में 'खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा' की ओर बढ़ने की भारत की इच्छा के बारे में बात की गई है। पोषण सुरक्षा का मतलब हर व्यक्ति के लिए संतुलित आहार, साफ़ पानी, सुरक्षित वातावरण और स्वास्थ्य सेवाओं (रोकथामी और उपचारात्मक) की उपलब्धता को शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सुनिश्चित करना होता है। नीति निर्माण के दृष्टिकोण से पहुंच, जागरूकता और कम से कम मूल्य पर अधिकतम उपलब्धता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विकास का मूल्यांकन करते समय पोषण के लिए किए जाने वाले प्रयासों और उनके परिणामों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और ऐसा मानकर नहीं चलना चाहिए कि यदि आर्थिक और औद्योगिक प्रगति हो गई तो लोगों को ये लाभ तो अपने आप ही मिल जाएंगे। समुचित पोषण, संयुक्त राष्ट्र संधारणीय विकास लक्ष्य 2 के साथ भी सुसंगत है जो 2030 तक अपने सभी रूपों में भूख को समाप्त करने और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए टिकाऊ समाधान विकसित करना चाहता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर जगह हर किसी को स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध हो । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भोजन की बेहतर उपलब्धता और संधारणीय (टिकाऊ) कृषि के व्यापक प्रचार की आवश्यकता होगी।

भारत खाद्य प्रसंस्करण में विश्व का नेतृत्व करने की इच्छा रखता है और नॉन-एल्कोहलिक बेवरेज बेवरेज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का एक मुख्य घटक है। इस सेक्टर के विकास के लिए चार सबसे बड़ी चुनौतियां हैं (क) असंगठित क्षेत्र और नकली उत्पादों से अन्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा (ख) उद्योग के संबंध में नकारात्मक धारणाएं (ग) जीएसटी और "पाप-कर" और (घ) अवसंरचना संबंधी मुद्दे।

खाद्य सुरक्षा नियामक प्राधिकरण, वसा, नमक और चीनी की उच्च मात्रा वाले खाद्य पदार्थों (HFSS खाद्य पदार्थों) की पहचान करने में लगे हुए है और भारत में खाद्य सेक्टर के विकास को सुनिश्चित करने के साथ ही साथ निर्धनतम व्यक्तियों पर कर का अनुचित बोझ और भी कम करने के लिए राजकोषीय नीतियों को इस दृष्टिकोण के अनुरूप व्यवस्थित किए जाने की सलाह दी जाती है । संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन (FAO) "संधारणीय खाद्य प्रणालियों" को ऐसी प्रणाली के रूप में मान्यता देता है जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण प्रदान करने के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय अभिप्रायों को कमजोर नहीं करती हों।इसका मतलब है कि: - यह पूरी तरह (आर्थिक स्थिरता की दृष्टि) से लाभदायक है; - इसका समाज के लिए व्यापक लाभ है (सामाजिक स्थिरता); और - इसका प्राकृतिक पर्यावरण (पर्यावरणीय स्थिरता) पर सकारात्मक या तटस्थ प्रभाव पड़ता है।

संगठित सेक्टर के विकास से उद्योग और अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद मिलती है। पाप-कर हमारे देश में सबसे ज्यादा गरीब लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने में सफल नहीं हुए हैं। औसत स्तर की कर-दर लागू करने से उपभोक्ताओं को स्वस्थ उत्पादों को अपनाने के लिए बढ़ावा मिल सकता है, विक्रेताओं की आय बढ़ाई जा सकती है और स्वास्थ्यकर उत्पादों की बिक्री आकर्षक मूल्य पर होने से सरकार के लिए अधिक राजस्व उत्पन्न किया जा सकता है। उपर्युक्त उपायों को लागू करने से खुदरा विक्रेताओं की आय को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

सुरक्षित और स्वच्छ उत्पाद मिलने से उपभोक्ताओं को फायदा होगा। असंगठित खुदरा सेक्टर के ग्राहक जब संगठित खुदरा सेक्टर की और आकर्षित होंगे तो इसका टर्नओवर बढ़ सकता है। सरकार भी अधिक राजस्व का लाभ उठा सकती है और संपूर्ण व्यवस्था को प्रगतिशील बनाने में मदद कर सकती है।

सरकार की "ईट राइट" पहल के अनुरूप, भारत को इस रणनीति को अपनाना चाहिए।

स्रोत:

- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8687666/
- Nutrition-related health taxes: setting expectations - J Jaime Miranda, Anne-Marie Thow, María Kathia Cárdenas, Camila Corvalán, Tonatiuh Barrientos-Gutiérrez, and Jay S Kaufman
- Miranda JJ, Thow AM, Cárdenas MK, Corvalán C, Barrientos-Gutiérrez T, Kaufman JS. Nutrition-related health taxes: setting expectations. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022 Feb;10(2):93-94. doi: 10.1016/S2213-8587(21)00325-9. Epub 2021 Dec 20. PMID: 34942086; PMCID: PMC8687666.
- Krishnamoorthy Y, Ganesh K, Sakthivel M. Fat taxation in India: A critical appraisal of need, public health impact, and challenges in nationwide implementation. Health Promot Perspect. 2020 Jan 28;10(1):8-12. doi: 10.15171/hpp.2020.04. PMID: 32104652; PMCID: PMC7036206. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7036206/
- https://www.thehindu.com/opinion/editorial/meeting-indias-aspirations-on-modis-ninth-i- day-speech/article65771986.ece
- Economic Survey 2023 (Chapter 8)
- https://gstcouncil.gov.in/sites/default/files/CEA-rpt-rnr.pdf Report on the Revenue Neutral
- Rate and Structure of Rates for the Goods and Services Tax (GST) December 2015
- https://www.investopedia.com/terms/l/laffercurve.asp#:~:text=The%20Laffer%20Curve%20shows%20the,disincentives%20workers%20from%20earning%20wages.
- Contribution of Non-Alcoholic Beverage Sector to Indian Economic Growth and Atmanirbhar Bharat - Arpita Mukherjee, Eshana Mukherjee, Vishnu Menon